

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 288 बेमेतरा, रविवार 14 जून 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

ढाई वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में हुए व्यापक विस्तार से स्वास्थ्य सेवाएं हुई सुदृढ़ : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने एनएचएम कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होकर एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एनएचएम कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साय ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में एनएचएम कर्मियों का योगदान अतुलनीय है और सरकार उनके कार्यों का सम्मान करती है। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब



एनएचएम के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में, जहां सड़कें और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मी पैदल चलकर, नदी-नाले पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने

विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और अब तक लगभग 90 प्रतिशत आबादी की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के साहसिक प्रयासों से बस्तर में

नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ है। अब यहां विकास और जनकल्याण की नई संभावनाएं खुल रही हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में हुए व्यापक विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ी है और सभी के सहयोग से विकसित एवं स्वस्थ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से इसी समर्पण और सेवा भावना के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जशपुर से लेकर सुकमा तक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान बनीं महक नरवासे : मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजनांदगांव जिले की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे ने सोजनी मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा सांसद बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए टी-20 एवं वनडे दोनों टीमों का उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर महक नरवासे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर महक का सम्मान किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महक नरवासे की यह उपलब्धि केवल उनके परिवार या राजनांदगांव जिले की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और प्रेरणा का



विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रही हैं। महक ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जो प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायी है।

संक्षिप्त समाचार

खराब मौसम के कारण रेवत रेड्डी की उड़ान हैदराबाद के बजाय बेंगलुरु मुड़ी



हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवत रेड्डी को लेकर हैदराबाद आ रही उड़ान को खराब मौसम के कारण बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास करीब दो घंटे तक तेज बारिश, गरज और बिजली चमकने का दौर जारी रहा। खराब मौसम और तेज हवाओं को देखते हुए एहतियातन हवाई अड्डे पर विमानों की लैंडिंग अस्थायी रूप से रोक दी गयी। मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद शाम 6:30 बजे इंडिगो की उड़ान से रवाना हुए थे।

ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में तृणमूल विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी



नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़ी सात जगहों पर तलाशी ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला है कि मित्रा ने कथित तौर पर बिचौलियों के जरिये नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली थी। यह रिश्वत कामराहटी नगरपालिका सहित कई नगरनिगम पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कराने के लिए ली गयी थी। ईडी ने मित्रा का संबंध ऐसी 125 से ज्यादा कथित गैर-कानूनी नियुक्तियों से जोड़ा है।

उत्तराखंड : राष्ट्रपति ने पहली बार किया नौ महिला कैडेट सहित 515 कैडेट की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण

देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उत्तराखंड के देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में पासिंग आउट परेड (पीओपी) का निरीक्षण किया और कैडेट की सलामी ली। आईएमए के चेतवुड हॉल के सामने ड्रिल स्कॉयर पर आयोजित 158वें सामान्य कोर्स एवं 141वें तकनीकी स्नातक कोर्स की परेड में 515 कैडेट पास आउट हुए। इनमें 481 भारतीय और 16 मित्र देशों के 34 अधिकारी कैडेट शामिल हैं। परेड की खास बात



यह रही कि आईएमए के 93 साल के इतिहास में पहली बार नौ महिला कैडेट पुरुष कैडेटों के साथ पास आउट हुईं और सेना में अधिकारी बनीं। मुर्मू ने अपने संबोधन में युवा अधिकारियों से कर्तव्यनिष्ठा और

देशसेवा को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। उन्होंने महिला अधिकारियों को विशेष बधाई दी और इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। इस अवसर पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे।

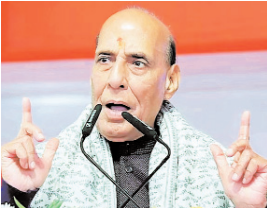
वायु सेना का ए न 32 मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त



नयी दिल्ली। वायु सेना का एक माल वाहक विमान ए एन 32 शनिवार को असम के जोरहाट वायु सेना स्टेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायु सेना ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है, हालांकि इसके अलावा अभी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। वायु सेना ने कहा है कि दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह मालवाहक विमान जोरहाट वायु सेना स्टेशन पर उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सूत्रों ने बताया है कि विमान के उतरते समय इसमें आग लग गयी, जिससे यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में जान माल के नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

भविष्य के युद्ध तकनीक, गति और नवाचार से लड़े जायेंगे : राजनाथ

हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारतीय वायु सेना के नये कमीशन प्राप्त अधिकारियों से उन्नत तकनीकों, नवाचार और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से संचालित युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।



हैदराबाद के पास वायु सेना अकादमी में 217वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा करते हुए सिंह ने स्नातक कैडेटों को अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और अपने प्रतिष्ठित 'विंग्स' हासिल करने पर बधाई दी। परेड को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि स्नातक होने वाले इस बैच में 240 पायलट और ग्राउंड-ड्यूटी अधिकारी शामिल हैं। इनमें भारतीय वायु

सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम के प्रशिक्षु भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अकादमी में विभिन्न शाखाओं की यह विविधता, सशस्त्र बलों के थल, वायु और जल सेना के जुड़ाव तथा एकीकृत अभियानों पर दिये जा रहे बढ़ते जोर को दर्शाती है।

भारतीय वायु सेना की समृद्ध विरासत का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इस बल ने 1947-48 के कश्मीर संघर्ष के दौरान एयरलिफ्ट अभियानों से लेकर

1971 के युद्ध तक, देश के हितों की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभायी है। उन्होंने आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ हालिया अभियानों में वायु सेना के योगदान की भी सराहना की और कहा कि ऐसे अभियानों की सफलता इसके कर्मियों के साहस, अनुशासन और पेशेवर रुख के कारण ही संभव हो सकी, जिसे उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी पूरा सहयोग मिला। रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध के तौर-तरीकों में बुनियादी बदलाव आया है। सैनिकों और हथियारों वाले पारंपरिक संघर्षों के विपरीत, आधुनिक लड़ाइयां तेजी से उपग्रहों, ड्रोन, सेंसर, रोबोटिक्स और साइबर सिस्टम जैसी तकनीकों पर निर्भर होती जा रही है।

सूर्योदय से पहले अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस टीम, मकसद अस्पष्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के एक बड़े दल ने शनिवार तड़के तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचकर राजनीतिक हलकों में नयी अटकलों को जन्म दे दिया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब बनर्जी विभिन्न मामलों में चल रही जांचों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पुलिस दल शनिवार तड़के करीब तीन बजे पटुआपाड़ा स्थित आवास पर पहुंचा। उनके साथ केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद थे, जिन्हें घर के बाहर तैनात रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक घर के लोगों को आवाज लगायी और इंतजार करने के बाद उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति मिली। सूत्रों के अनुसार, दल में शालबनी थाने के अधिकारी भी शामिल थे। महिला



बाहर कई पुलिस वाहन खड़े रहे और अधिकारी चार घंटे से अधिक समय तक परिसर के भीतर मौजूद रहे। सुबह सात बजे के बाद कुछ अधिकारी बाहर निकले और आपस में चर्चा करने के बाद फिर आवास के भीतर चले गये। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब दो दिन पहले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने बनर्जी से भवानी भवन में साढ़े पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर वह गुरुवार शाम जांचकर्ताओं के समक्ष उपस्थित हुए थे।

पुलिसकर्मों भी पुलिस टीम का हिस्सा थीं।

पुलिस किस मामले के सिलसिले में बनर्जी के आवास पर पहुंची थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आवास के

ममता ने पुलिस पर अभिषेक के घर का ताला तोड़कर तलाशी लेने का लगाया आरोप

कोलकाता। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास का ताला तोड़कर घर की तलाशी ली।



आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बनर्जी ने कहा, पुलिस ने ताला तोड़ा और पूरे घर की तलाशी ली। यह अभूतपूर्व है। अदालत के निर्देशों के बावजूद वे अंदर घुसे और छापेमारी की। हम इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह आरोप तब सामने आया, जब शनिवार तड़के राज्य और कोलकाता पुलिस के जवानों की एक बड़ी टुकड़ी कालीघाट के

पटुआपारा में बनर्जी के आवास पर पहुंची। काफी देर तक अंदर मौजूद लोगों को आवाज देने के बाद पुलिस ताला तोड़कर परिसर में दाखिल हो गयी और व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान आवास के बाहर केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों को तैनात किया गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पुलिस की टीम तड़के तीन बजे के तुरंत बाद पहुंची थी और उनके साथ केंद्रीय बल भी मौजूद थे। अधिकारियों ने जब घर के अंदर दाखिल होने का प्रयास किया, तब आवास के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं।

प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर मैं 13-18 जून तक फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करूंगा

फ्रांस, स्लोवाकिया यात्राओं से यूरोप तथा जी-7 समूह के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे: मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि फ्रांस और स्लोवाकिया की उनकी यात्राओं से यूरोप और जी-7 समूह के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया की छह दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले शनिवार को एक वक्तव्य में कहा कि उनकी ये यात्राएं यूरोपीय महाद्वीप और उससे आगे भी भारत की साझेदारियों का दायरा बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता की भी बताती हैं। मोदी ने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों और स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर मैं 13-18 जून तक फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करूंगा। उन्होंने कहा, भारत के रणनीतिक

दृष्टिकरण में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत का दौरा किया था, तब हमने अपने संबंधों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया था। जब मैं नीस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलूंगा, तो हम फ रवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और अपने सहयोग के अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। मैं आपसी हित के अहम वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मोदी ने कहा कि वह फ्रांसीसी शहर नीस में 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ 'भारत इनोवेट्स' प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' के तहत आयोजित होने वाला यह अहम कार्यक्रम भारत के सबसे होनहार



स्टार्टअप को वैश्विक निवेश से जोड़ेगा और भारत के उच्च शिक्षा इकोसिस्टम से निकलने वाले नवाचारों के लिए एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके बाद वह 14-15 जून को राजकीय यात्रा के लिए स्लोवाकिया जाएंगे। वर्ष 1993

में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। यह ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में बनी मजबूत गति को और आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा, मैं ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति पेलोग्रिनी और प्रधानमंत्री फि को के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे स्लोवाकिया के प्रमुख व्यापारियों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। मोदी ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से संबंधों में आयी गति को आगे बढ़ाते हुए, यह यात्रा यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि वह स्लोवाकिया से वापस फ्रांस के शहर

एवियन लॉरेंट और 16-17 जून को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा, जी-7 में भारत की मौजूदगी हमारे सहयोगियों के हम पर भरोसे और हमारी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाती है। यह लगातार आठवां जी-7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। जी-7 में भारत न केवल अपनी बात रखेगा, बल्कि 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की आकांक्षाओं को भी आवाज देगा। मैं 18 जून को पेरिस में अपनी फ्रांस यात्रा का समापन करूंगा, जहां मैं राष्ट्रपति मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 में शामिल होंगा। विवा टेक तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है।

विचार-पक्ष

संपादकीय

ऐसा लगता है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अथवा अन्न सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। घरेलू खास मिलेन्द्र की कीमतों में तीनों महीनों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य नहीं हो पाए का असर अब प्रत्यक्ष रूप से महंगाई में तेज बढ़ोतरी के रूप में सामने आ रहा है। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार इजाफ़ा के बाद सरकार ने घरेलू रसोई गैस के दामों में भी २९ रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी कर दी है। यानी महंगाई की

आंच आम लोगों की रसाई तक पहुँच गई है, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। इस स्थिति की लेकर पहले से ही अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन सवाल सरकार के उन दावों पर उठ रहा है, जिनमें कहा गया था कि संभावित संकट का सामना करने के लिए समय रहते वैकल्पिक उपाय तलाश लिए जाएंगे। दरअसल, होमुजु जलमार्ग के बाधित होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऊर्जा का संकट

खड़ा हो गया है। भारत पर इसका ज्यादा असर इसलिए पड़ रहा है, क्योंकि यहां आयात पर निर्भरता अधिक है। यह सब ज्ञात होने के बावजूद अगर महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल दिया जाए, तो क्या इसे उचित ठहराया जा सकता है। सरकार ने पिछले माह चरण में पेट्रोल-डीजल के माला बढ़ाए थे, जिसके परिणामस्वरूप कुल डिमांड पर पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये प्रति लीटर

महंगा हो गया था। इसी तरह व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में भी बड़ोतराई गई। उम्मीद की जा रही थी कि घरेलू सिलेंडर गैस सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अब सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में तीन महीनों में दूसरी बार बड़ोतराई की गई है। इससे पहले मार्च में साठ रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी, यानी इस अवधि में प्रति सिलेंडर कुल मिलाकर 89 रुपये

बढ़ चुके हैं। सरकार का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में कीमतों में लगातार उछाल की वजह से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दाम घटते हैं, तो क्या उनका लाभ आम उपभोक्ताओं को दिया जाता है? यह मामला लंबे समय से कई स्तरों पर उठता जाता रहा है, लेकिन इस पर कोई गंभीरता अब तक नजर नहीं आई है। हैदराबाद रसाई गैस सिलेंडर के दामों में

बदौतीरी के बाद सरकार अब यह कहकर अपनी नीत थपका रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद देश की जनता को रसोई गैस दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विवर्धनी ही कहा जाएगा कि एक तरफ आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अब भी नियंत्रण में हैं।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का नाम ही एक नकारात्मक और व्यंग्यात्मक मानसिकता का परिचायक है। किसी राजनीतिक दल की नकल करते हुए स्वयं को कॉकरोच के प्रतीक से जोड़ना लोकतांत्रिक विमर्श को गंभीरता से अधिक तमामशे में बदलने का प्रयास प्रतीत होता है। लोकतंत्र में व्यंग्य का स्थान है, लेकिन व्यंग्य यदि विचार का स्थान ले ले, तो वह जनमत को भ्रमित भी कर सकता है। किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन उसकी मांगों और कार्यप्रणाली से किया जाता है। सीजेपी की प्रमुख मांगें हैं- परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक की रोकथाम, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

लोकतंत्र का व्यंग्य या लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर संकट?

(ललित गर्ग)

किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन उसकी मांगों और कार्यप्रणाली से किया जाता है। सीजेपी की प्रमुख मांगें हैं-परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक की रोकथाम, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इनमें से अधिकांश मांगें ऐसी हैं जिन पर देश का हर जिम्मेदार नागरिक सममत हो सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह केवल मतदान की व्यवस्था नहीं, बल्कि संवाद, सहमति, असहमति, संश्लेषणात्मक मर्यादाओं और सामाजिक उत्तरदायित्वों का एक संस्कृत तंत्र है। लोकतंत्र की शक्ति विरोध में निहित है, लेकिन उसकी गरिमा विरोध की शैली, उद्देश्य और मर्यादा से निर्धारित होती है। हाल के दिनों में चर्चित हुई तय्याकशित 'काँकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) इसी संदर्भ में गंभीर विमर्श की मांग करती है। यह आंदोलन प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध के नाम पर उभरा। प्रारम्भ में यह सोशल मीडिया पर व्याख्यात्मक अभियान के रूप में सामने आया और बाद में दिल्ली के जंतर-मंतर तक पहुंच गया। इसके सभायात्रियों ने इसे युवाओं के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह वास्तव में शिक्षा सुधार का आंदोलन है या लोकतांत्रिक अस्तोष का व्यंग्य, उपहास और राजनीतिक धुवीकरण की दिशा में मोड़ने वाला एक नया प्रयोग? भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। किंतु कोई भी आक्रोश निरंकुश नहीं होता। लोकतंत्र में विरोध का उद्देश्य समाधान की खोज होना चाहिए, न कि अराजकता का विस्तार। यदि विरोध का स्वर केवल उहास, आक्रोश और टकराव तक सीमित रह जाए, तो वह लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर करने लगता है। 'काँकरोच जनता पार्टी' का नाम ही एक नकारात्मक और व्याख्यात्मक मानसिकता का परिचायक है। किसी राजनीतिक दल की नकल करने हुए स्वयं को काँकरोच के प्रतीक से जोड़ना लोकतांत्रिक विमर्श को गंभीरता से अधिक तमारा में बदलने का प्रयास प्रतीत होता है। लोकतंत्र में व्यंग्य का स्थान है, लेकिन व्यंग्य यदि विचार का स्थान ले ले, तो वह जनमत को भ्रमित भी कर सकता है। किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन उसकी मांगों और कार्यप्रणाली से किया जाता है। सीजेपी की प्रमुख मांगें हैं-परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक की रोकथाम, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इनमें से अधिकांश मांगें ऐसी हैं जिन पर देश का हर जिम्मेदार नागरिक सहमत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मांगों को मनवाने का तरीका भी उसना ही जिम्मेदार है? क्या काँकरोच के आवुठे पहनना, राजनीतिक व्यंग्य को आंदोलन का आधार बनाना और सोशल मीडिया पर उजेक

The logo for the Cockroach Janta Party is centered on a white background with orange and green wavy borders at the top and bottom. At the top, a cockroach wearing black sunglasses stands on a small brown podium. Behind the cockroach is a circular emblem with orange, white, and green concentric rings. Below the podium, the word "COCKROACH" is written in large, bold, black capital letters. Underneath that, the words "JANTA PARTY" are written in green capital letters, flanked by two horizontal orange lines. On either side of the central text, there are silhouettes of a crowd of people with their arms raised in celebration.

प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना शिक्षा सुधार की चुनौती परिवर्तन की सशक्त व्यवस्था है। यहां सरकारें जनमत से बनती और बदलती हैं। इसलिए भारत के युवाओं को विदेशी या पड़ोसी देशों के आंदोलनों की भावनात्मक तुलना के बजाय भारतीय लोकतांत्रिक विरोधवादीओं को समझना चाहिए। हर देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं। इसलिए विदेशी उदाहरणों के आधार पर भारत में असंतोष को भड़काना न तो बौद्धिक रूप से उचित है और न ही राष्ट्रीय हित में। आज सोशल मीडिया और भी विचार को कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता और वैश्वता एक जैसी चीजें नहीं हैं। कई बार कोई विचार ट्रेंड हो बन जाता है, लेकिन उसके पास न स्पष्ट दृष्टि होती है, न कोई रचनात्मक कार्यक्रम और न कोई उत्तरदायित्व। सोशल मीडिया पर वायरल होना लोकतांत्रिक स्वीकृति का प्रमाण नहीं है। 'कॉकरोच जनता पर्व' का तेजी से लोकप्रिय होना इस बात का संकेत अवश्य है कि युवाओं में असंतोष है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आंदोलन का मार्ग सही है। लोकतंत्र में ट्रेडिंग हैस्टेट्स से अधिक महत्व तथ्यों, नीति और संस्थागत संवाद का होता है। यदि राजनीति केवल मीम, व्यंग्य और डिजिटल आक्रोश तक सीमित हो जाए तो लोकतंत्र धीरे-धीरे विचारशील नागरिकता से हटकर भावधर्म में बदल सकती है। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता, संस्थागत विश्वास और राष्ट्रीय एकता का भी है। यदि युवा शक्ति का बड़ा हिस्सा निरंतर अविश्वास, नकारात्मकता और टकराव की राजनीति की ओर आकर्षित होता है, तो यह लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। विकास के लिए केवल आलोचना नहीं, बल्कि सभागतिता भी

आवश्यक है। युवाओं को सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें जवाबदेही मांगनी चाहिए, लेकिन संस्थाओं के प्रति सम्मान भी बनाए रखना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता विरोध और संयोग के संतुलन में निहित है। इस पूरे प्रकरण का एवम महत्वपूर्ण पक्ष उन राजनीतिक दलों और नेताओं की भूमिका है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे आंदोलनों को समर्थन देते दिखाई देते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल वास्तव में शिक्षा सुधार चाहता है तो उसे संसदीय विधानसभाओं और नीति मंचों पर ठोस प्रस्ताव रखने चाहिए। लेकिन यदि छत्र असंतोष को केवल सरकार को घेरने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र और युवाओं दोनों के साथ अन्याय है। राजनीतिक दलों की स्पष्ट करना चाहिए कि वे शिक्षा सुधार के लिए क्या ठोस कार्यक्रम रखते हैं। केवल विरोध का समर्थन करना पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व विकल्प प्रस्तुत करना भी होता है। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता, पेपर लीक पर कठोर दंड, रोजगार सृजन, शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार-ये सभी वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन इनका समाधान व्यंग्यात्मक राजनीति या प्रतीकात्मक आक्रोश में नहीं है। समाधान सकार, न्यायपालिका, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, छात्र संगठनों और समाज के बीच निरंतर संवाद में है। आवश्यकता सत बात को है कि युवाओं के असंतोष को रचनात्मक ऊर्जा में बदला जाए। भारत का लोकतंत्र विरोधों को स्वीकार करता है, लेकिन वह विरोध तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था को तोड़ने के बजाय सुधार के प्रद्विष्टियां पहली दृष्टि में लोकतांत्रिक व्यंग्य और असंतोष की अभिव्यक्ति लग सकती हैं, लेकिन इनके दूरगामी प्रभावों की गंभीर समीक्षा आवश्यक है। यह राजनीति उपाहास, प्रतीकात्मक आक्रोश और डिजिटल उतेजना तक सीमित हो जाएगी, तो लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता प्रभावित होगी। भारत को आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो प्रश्न भी पूछें और समाधान भी खोजें। जो विरोध भी करें और धार निर्माण में भागीदारी भी निभाएं। लोकतंत्र की शक्ति संघर्ष में नहीं-संवाद में है। विभाजन में नहीं-समन्वय में है और तात्कालिक उतेजना में नहीं-दीर्घकालिक राहद्वि में है। इसलिये समय की मांग है कि युवा, राजनीतिक दल और समाज सभी मिलकर यह विचार करें कि क्या 'कॉकरोच राजनीति' वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करेगी, या फिर वह भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति, राजनीतिक मर्यादाओं और विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प के सामने एक नई चुनौती बनकर उभरेगी। यही प्रश्न आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। है।लेखक, पत्रकार एवं स्वतंत्रकार है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

विकसित भारत का सपना और प्राथमिक शिक्षा की हकीकत

पहली नजर में यह दूरस्थ इलाकों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रमाण लगता है, लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतने छोटे और अलग-थलग स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कैसे संभव होगा? बहुस्तरीय कक्षाएं, सीमित संसाधन, कभी शिक्षक की अनुपस्थिति, कभी विषय विशेषज्ञों का अभाव- ये सब मिलकर शिक्षा को सिर्फ बच्चों की उपस्थिति तक सीमित कर देते हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में यह चुनौती और गहरी हो जाती है, जहां कई स्थानों पर स्कूल भवन मौजूद हैं, लेकिन प्रयोगशालाएं नहीं हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट नहीं, पुस्तकालय हैं, नियमित पठन संस्कृति नहीं।

(कुमारसिद्धार्थ)
देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का लेकर हाल के वर्षों में आई विभिन्न रिपोर्ट में यही संकेत दिया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता आज भी चिंता का विषय बनी हुई है।

निद्यालय को कलत्र शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे जीवंत प्रवेश-द्वार भी माना जाता है। देश ने पिछले चार दशक में स्कूली शिक्षा के विस्तार को एक लंबी यात्रा के रूप में देखा है। गांव-गांव स्कूल पहुंचे, नामांकन बढ़ा, बालिका शिक्षा में सुधार हुआ, बिजली, शौचालय, कंप्यूटर और स्मार्ट कक्षाओं जैसी सुविधाएं बढ़ीं। मध्यह्रद भोजन, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रवृत्तियां, स्कूल परिवहन, डिजिटल संसाधन और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं ने शिक्षा के विस्तार को गति दी है। मगर इस पूरी कवायद में एक महारा अभाव आज भी दिखाई देता है और वह है शिक्षा की गुणवत्ता।

इस संदर्भ में देखें तो वर्तमान में देश में लगभग 14.7 लाख सरकारी स्कूल, 24 करोड़ से अधिक विद्यार्थी और करीब एक करोड़ शिक्षक हैं। आकार के लिहाज से यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। मगर इतनी विशाल व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन भवनों, योजनाओं और नामांकन से नहीं, बल्कि इस कसौटी पर होना चाहिए कि क्या बच्चों को वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है?

नीति आयोग की ओर से हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने स्कूलों तक पहुंच की लड़ाई काफी हद तक जीत ली है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लड़ाई अब भी अधूरी है।

पिरोट से पता चलता है कि देश में आज भी एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के कमजोर भाग का आईना है। इन स्कूलों में एक ही शिक्षक पहली से पांचवीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जिसके ऊपर मध्याह्न भोजन की निगरानी, सरकारी प्रशालीक पर डेटा अपलोड करने और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि शिक्षक सिर्फ पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाते, वे सीखने का वातावरण भी रचते हैं। वे जिज्ञासा को दिशा देते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास जगाते हैं और कक्षा को संवाद का जीवंत मंच बनाते हैं। मगर जब वही शिक्षक मूल उद्देश्य से इतर कार्यों में उलझ जाता है, तब ही बच्चों में ज्ञान का संवाद स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है। शिक्षा तब सीखने और सिखाने के बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने की प्रक्रिया बनकर रह जाती है।

नीति आयोग की रिपोर्ट का एक अन्य पहलू छोटे स्कूलों पर केंद्रित है। देश के लगभग 35 फीसद विद्यालयों में पचास से कम विद्यार्थी हैं। इनमें से



हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहाँ दस से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। पहली नजर में यह दूरस्थ इलाकों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास लगता है, लेकिन यह सवाल उठता स्वाभाविक है कि इतने छोटे और अलग-थलग स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कैसे संभव होगा? बहुस्तरीय कक्षाएँ, सीमित संसाधन, कभी शिक्षक की अनुपस्थिति, कभी विषय विशेषज्ञों का अभाव- ये सब मिलकर शिक्षा को सिर्फ बच्चों की उपस्थिति तक सीमित कर देते हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में यह चुनौती और गहरी हो जाती है, जहाँ कई स्थानों पर स्कूल भवन मौजूद हैं, लेकिन प्रयोगशालाएँ नहीं हैं। नौचकल कंप्यूटर हैं, इंटरनेट नहीं, पुस्तकालय नहीं, नियमित पठन संस्कृति नहीं। यानी शिक्षा का ढाँचा खड़ा है, पर उसके भीतर सीखने की आत्मा अभी भी कमजोर दिखाई देती है।

देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाल के वर्षों में आई विभिन्न रिपोर्ट में यही संकेत दिया गया है कि

शिक्षा की गुणवत्ता आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। तोसरी-चौथी कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ सहेजता से नहीं पढ़ पा रहा। पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक बड़ा हिस्सा सरल भाग, प्रतिशत या अनुपात जैसी गणितीय गणितयी समझ में संघर्ष करता दिखाई देता है। इसलिए स्कूलों में केवल नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि सीखना कक्षा का असली पैमाना है। इसके स्थिति उस बुनियादी संकेत का संकेत है, जो आगे चलकर माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार क्षमता की सीढ़ियों को प्रभावित करता है। जब नींव कमजोर होती है, तो आगे की पूरी शैक्षिक संरचना अस्थिर हो जाती है। यही कारण है कि आज उद्योग जगत भी युवाओं को न केवल के अभाव की बात करता है।

दो दशक पहले की बात की जाए, तो तब देश के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। मगर आज स्थिति बदल रही है। वर्ष 2005 में जहां

नगभग 71 फीसद बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 49.24 फीसद रह गया है। यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात आधे से नीचे चला गया है।

ग्रामीण परिवार, जो कभी सरकारी
वेद्यालय को स्वाभाविक विकल्प
नहीं थे, अब सीमित आय के बावजूद
नेजी स्कूलों की ओर देख रहे हैं। यह
कमल विकल्प में परिवर्तन नहीं,
बल्कि भरोसे के संकट को दर्शाता है।
अधिकांशक अवसर अग्रणी माध्यम,
अनुशासन, नियमित उपस्थिति और
अभ्यासकृत बेहतर जवाबदेही को निजी
स्कूलों से जोड़कर देखते हैं, भले ही
वास्तविक गुणवत्ता हर जगह समान
नहीं। यह प्रणति विशेष रूप से
चुंटाजनक है, क्योंकि सरकारी
वेद्यालय ही सामाजिक न्याय, अवसर
की समानता और लोकतांत्रिक शिक्षा
के सबसे बड़े माध्यम रहे हैं। यदि इन
संस्थानों पर भरोसा कम होता है, तो
शिक्षा के साथ लोकतंत्र की बुनियाद भी
कमजोर होती है।

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल तक लाने में तो सफलता मिली है, लेकिन जैसे-जैसे कक्षाएं ऊपर की ओर जाती हैं, बच्चे छूटते जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर ग्यारह फीसद से अधिक है। विशेष रूप से लड़कियां,

मादित्वासी समुदाय और प्रवासी एवं
नार्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे
को बर्बाद करने स्कूली शिक्षा से बाहर होते
हैं। इसके पीछे केवल आर्थिक कारण
नहीं हैं, बल्कि किशोरावस्था में
सामाजिक दबाव, बाल विवाह,
शिक्षण परिवर्तन की कमी, विज्ञान और
गणित शिक्षकों का अभाव, स्थानीय
स्तर पर करिअर मागदर्शन की कमी
और परिवारों का जागरूक न होना भी
संकेत की गहरा करता है। इसके
अलावा शिक्षकों के खाली पद वर्गों तक
नहीं बरे जाते। कई राज्यों में अतिथि
शिक्षक और सिविद शिक्षक व्यवस्था
नो स्थायी समाधान बनाया जा रहा है।

एसे में शिक्षकों की समायबद्ध न्युक्ति, छोटे स्कूलों का तर्कसंगत निर्माण, स्कूल नेतृत्व को मजबूत करना, डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग, सीखने के परिणामों की समयित निगरानी और शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण जैसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है। असली बदलाव तब आगा, जब जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर कक्षा-शिक्षक तक जवाबदेही की संस्कृति आकार लेगी। ब्रिटेन का यह है कि देश में शिक्षा सुधार का संकेत नीति का नाम और क्रियान्वयन का अधिकार है। योजनाएं बनती हैं, बजट वित्तवृत्त होते हैं, लक्ष्य तय होते हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर प्रभावी एवं समान रूप से नहीं दिखाई देता। भारत वर्ष किससि तरह बनने का पारता देख रहा है।

गटर के कॉकरोच !

कभी बॉलीवुड के शहशाह अमिताभ बच्चन सिल्वर स्क्रीन पर कॉकरोच को लेकर शानदार कॉमेडी करते नजर आए थे। वे नशे में धुत होने के बाद कॉकरोच के सामने अपनी कलाई निकालते अभिनय कला का प्रदर्शन कर श्रुतकों को लुभाते देखे गए थे। तब हमारे देश की जनता ने उसे एक फिल्म का दृश्य मानकर बाद आई...गई, हो गई कि तर्ज पर भुला दिया था। अब वही कॉकरोच एक बड़ी क्रांति के रूप में राजनीतिक गलियारों में कभी सीधा तो कभी उल्टा पलटकर सीधा होने के प्रयास में बिखरे - बिखरे टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास करता दिख रहा है। जिस कॉकरोच को दूर से देखकर ही महिलाएं चौंक पड़ती हैं, आज उसी कॉकरोच को पश्चिम बंगाल की तड़पती आत्मा और विदेशी धरती से भारत वर्ष की संस्कृति में पदार्पण करने वाली नेत्री ने अपने सुकोमल हाथों से सहलाना शुरू किया है। क्या अब कॉकरोच भयाक्रांत करना छोड़ चुके हैं? या फिर कॉकरोच को ही टुकड़े - टुकड़े दलों ने मजबूत जोड़ वाले फेनिका के रूप में स्वीकार कर लिया है? हमारे देश में सब एक बड़ा सवाल यही नहीं है गरीब और औसत दर्जे वाले परिवारों को महंगाई से राहत कैसे और कब दिलाई जा सकेगी? हमारे देशवासियों को चपत्ते के लिए अच्छी सड़कें कब मिल पाएंगी? बेरोजगारी का मंजर कब हमारे देश का पीछ छोड़ेगा? राष्ट्रीय चिंता के रूप में सबसे बड़ी फिक्र इस बात की है कि कॉकरोच जनता पार्टी - (सी जे पी) किस दल के साथ गबंधन करेगी?

मेरी कल्पना सोचती है कि ये वही कारोबार है, जिन्हें हम अपनी रसोई से बाहर भागने तरह- तरह के जतन करते आ रहे हैं। क्या मजाल कि कोई दवा (ड्रिग्स सहित) इन्हें भगा सके। ये कारोबार के हमारे सोच का इंजकार करते रहते हैं। जैसे ही घरों की लाइटें बंद लुटें - अंधेरा इन्हें ऐसे एकत्र करता है, मानो कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रात व गैस चूल्हों पर पूरी संसद एकत्र हो गई है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए छोट- बड़े, दुबले - पतले , भारी - भरकम शरीर वाले कॉन्फेकरों अपनी - अपनी किता प्रकट कर रहे हैं। इनकी आत्मा से निकलने वाली आवाजें एक साथ ऐसा संगीत बनाती हैं, जिनके आगे हमारी नींद भी हार जाती है। एक युवक के दिमाग की उपज ने रातों - रात कारोबार जना पार्टी बनाकर यहाँ - वहाँ भटक रहे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी जल्द ही सोशल मीडिया पर लॉन्च किए जाने की तैयारी है। कुछ का मानना है कि चुनाव चिन्ह ऐसा होगा जो आम जनता को भावनात्मक रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सके। मसलन - * मोटा भाई की चप्पल से बचा हुआ कारोबार। * कुछ कारोबारियों को यह जगह बगदारी भी सौंपी गई है कि वे एक अच्छा सा नारा तैयार करें, जो मतदाताओं को बरगला सके। यह सुनने में आ रहा है कि एक संत से भय खाते हुए कॉन्फेकरों के सदसद ने एक नारा तैयार भी कर लिया है। वह कुछ इस तरह बताने का खुदा है - * हिंदुस्तान के हर घर की रसोई हमारी बंकर होगी, बिकास के लिए नालियों और जलदाओं का निर्माण होगा। * अभी इस नारे पर मुह लगराना बाकी है।

चनुन की बिसात पर जौत का आधार थाय: पाटियों का घोषणा पर बनता आ रहा है । इसे मुख्य मुद्दा बनाते हुए कॉकरोच पार्टी से जुड़े एक पुराने दल के तोतानुमा नका वाले नेता ने अपना घोषणा पत्र कुछ इस तरह बनाकर बंध लिया है । उस नेता ने सबसे पहला पॉइंट कॉकरोचों की पसंद के अनुसार अंधेरे को चुनते हुए कहा है कि हमारी सत्ता आते ही सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन अंधेरे का साम्राज्य होगा । वह इसलिए ताकि कॉकरोच हर घर में शांति के साथ सम्मान पूर्वक अपना स्थान बना सकें । मैकिल स्टोर्स से लेकर किच वस्तु की दुकान और मनिहॉली दुकानों पर बची जाने वाली हिट अथवा लाल रंग की उन दवाओं पर प्रतिबंध होगा जिससे कॉकरोचों का जीवन संकट में पड़ता हो । हर रसोई में रात के बचे हुए भोजन को तरीके से रखने का दिशा निर्देश जारी करते हुए उक्त भोजन को कॉकरोच राष्ट्रीय भोजन का नाम दिया जायेगा । किसी भी आम और खास के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह रात्रि के दौरान किसी भी वक्त लाल जला सकें ! इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी ! पार्टी का हर राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर का अधिवेशन किसी पुराने और जर्जर गोदाम में ही सम्पन्न किया जाएगा ताकि कॉकरोचों को बैठने के लिए स्थान की कमी न हो । वे दीवारों की दरार में घुसकर भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का भाषण आसानी से सुन सकें ! कॉकरोचों के अस्तित्व पर रहाई से मंथन करते हुए सत्ता से बाहर भटसके रहे राजनीतिकार काने गठबंधन करते हाथ - पांव मारते दिखाई पड़ रहा है । उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कॉकरोच कभी खत न लेंगे ! बड़े से बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है । प्रधानमंत्री बदला जा सकता है । विचार धाराओं में समाज की मांग के अनुसार परिवर्तन आ सकते हैं । बावजूद इन सबके क्या मजाल कि कोई कॉकरोचों की सोच अथवा उनके अस्तित्व को मिटा सके ! कॉकरोच हर युग में जीवित थे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे । कॉकरोच प्रजाति की इसी अमरता से प्रभावित होकर अपनी राजनीति खो चुके नेता पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं ! मुझे डर है कि कहीं कॉकरोचों को देखकर अब मल्लिएं अपना डर छोड़कर उन्हें दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करना शुरू न कर दें ! कारण यह कि कौन सा कॉकरोच कब सांसद, विधायक या पाषांड बन जाय, कहा नहीं जा सकता है ! आजकल सोशल मीडिया ने कॉकरोच विचार को राजनीतिक व्यंग्य का स्वल्प प्रदान किया है । मिम्स के ज़रिए कुछ सच्चाई भी सामने आने लगी है । मसलन - ÷ हम वहीं ज़िंदा रहते हैं , जहाँ सिस्टम मर जाता है । हमारा मुख्यालय वहीं होता है , जहाँ वाईफ़ाई आसानी से चल पाए ! घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु भी सच आकर्षक नहीं है - पहले सरवाइव करेंगे , फिर विकास की ओर अग्रसर होंगे ! इन सबके बीच सबसे चर्चित लाइन बन गई है - जब देश को गटर बनाओगे , तो कॉकरोच ही पैदा होंगे !

डॉ.सूर्यकांत मिश्रा
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
9425559291.

दिया है कि जहा ईरान वर्ल्ड कप में खेलेगा, अगर उन स्टीडियम में अधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं किए गए झंडे लाए जाते हैं या राष्ट्रीय टीम के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, तो टीम मैनेजर निश्चित रूप से मैच रोकने के लिए जिम्मेदार होगा।

मंत्री ने आगे कहा कि ईरानी अधिकारियों को टीम के ग्रुप - स्टेज के आखिरी मैच को लेकर आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा, 'हमें भरोसा दिलाया गया है कि मिस्र के खिलाफ मुकाबले के दौरान स्टीडियम में कोई भी गड़बड़ वाली घटना नहीं होगी।'

ये टिप्पणियां टूर्नामेंट में ईरान की भागीदारी पर बढ़ती छानबीन के बीच आई हैं। अप्रैल में, पैक्यूब में फीफा कांग्रेस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए, जिन्होंने ईरान को वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग की। उनका तर्क था कि राष्ट्रीय टीम ईरानी लोगों के बजाय इस्लामिक रिवाय्यूशनरी गार्ड कॉर्पस का प्रतिनिधित्व करती है। मिस्र के खिलाफ ईरान के मैच ने भी तब ध्यान खींचा जब दोनों देशों के फुटबॉल संघों ने कथित तौर पर फीफा से खेल के दौरान एलजीबीटीक्यू + प्राइड से जुड़ी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया।



भारतीय टीम को हार मिली। इस पारी में भारतीय गेंदबाजों ने 15 रन एकस्ट्रा के दिए। यही 15 रन अंत में ड्रिडिया ए को मिली हार के बाद सबसे महंगे साबित हुए। भारतीय गेंदबाजों ने 25.5 ओवर की अफगान पारी में ही 15 अतिरिक्त रन खर्च कर दिए। इसमें 8 वाइड थीं और 7 रन लेग बाय के थे। यह 15 रन अगर बेबे होते तो शायद ड्रिडिया ए की टीम उकवर्थ लुईस से भी यह मुकाबला नहीं गंवानी।

अफगानिस्तान की अच्छी बल्लेबाजी - अफगानिस्तान की शुरुआत इस मैच में अच्छी रही। हसन ईसाखिल ने तेज बल्लेबाजी की और 29 गेंद पर 34 रन बनाए। उन्होंने शुरु से ही तरनट बड़ा कर रखा। दूसरे ओपनर क़ामरु इमरान भी मीर क़ाज ए पर डेरे रहे और 75 रन बनाकर नाबाद रहे। चौथे नंबर पर आए बाहिर शाह ने भी नाबाद 51 रन बनाए।

